

+
C
M
Y
K
दैनिक विश्व परिवार

डबल इंजन की सरकार में विकास की रपतार भी डबल

केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका की ओर छत्तीसगढ़

रायपुर (विश्व परिवार)। केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्य में श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता को दोहरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस संकल्प के साथ विस्तृत भारत की प्रतिबद्धता जाहिर की ओर बढ़ाए हुए छत्तीसगढ़ में भी जानहित कार्यों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। साय सरकार में गुणवत्ता, जवाबदेही और पारिवर्तीय के तीन कार्यसंभवता के जरिए लोगों तक सुशासन का संदेश जारी रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में संचालित योजनाओं का छत्तीसगढ़ को भरपूर लाभ मिल रहा है। केन्द्र की प्रमुख योजनाएँ जिनका क्रियान्वयन और उनका लाभ प्राप्त हितप्राप्ति को दिलाने में छत्तीसगढ़ लगातार आगणी भूमिका की ओर बढ़ रहा है। जिनमें पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पूरे देश में सर्वाधिक 8.46 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। भारतीय योजना के अंतर्गत 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे के पार 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को भी पक्का मकान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक पीएम आवास योजना ग्रामीण में 1 लाख 74 585 हितप्राप्ति को उनका आवास मिल चुका है। प्रदेश में पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को पीएम योजना का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में विशेष लिफ्टी जनजाति योजनों के 24 हजार 542 परिवारों को आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा 1 हजार 699 करोड़ की स्वीकृति से 2 हजार 449 किलोमीटर की 715 सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा, जिनसे 777 पीक्सीटीजी बसाइटें लाभान्वित होंगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। प्रदेश में लोगों को गुणवत्ता पूर्ण अधिकारिक स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, इस उपलब्धि के लिए भारत द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य के 266 सरकारी अप्यायों को क्राइली सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 11 लाख 20 हजार से ज्यादा मरीज आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2023 से नवम्बर 2024 तक 883 सर्विदा इन्डॉर्स पर नियुक्ति भी दी गई है।

डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में विकास की रफ़तर भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री सङ्करण योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के नवस्तर प्रभावित दूरसंचार को 103 बिलोमीटर लम्बाई की सड़कें बन चुकी हैं, इनमें 616 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य भी जारी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ ही छत्तीसगढ़ के 50 लाख परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुँचने का लक्ष्य की ओर बढ़ाए हुए 40 लाख परिवारों तक नल कनेक्शन पहुँचने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के लिए 11 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल चुकी है। उरगा-कटघोरा बाईपास, बसना से सारंगाढ़ फीडर रूट, सारंगाढ़ से रायपुर फीडर रूट और रायपुर-लखनादेव इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी केंद्र से स्वीकृति मिल चुकी है, 236.1 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाले इस कॉरिडोर को 9208 करोड़ रुपए की लागत बनाया जाएगा। केंद्रीय सङ्करण के एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 20 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ को पीएम ई-वर्षों के देखने और सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 240 ई-वर्षों की स्वीकृति भी मिली है, ये बारे रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में चर्चाएँ। इस सुविधा से आप लोगों को सस्ती दर में परिवहन की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का दोहरा फायदा पहुँच रहा है, किसान अपनी सुविधा से अधिकतम 5 लाख तक अल्पकालीन कृषि ग्राम भी ले सकते हैं। मोदी जी की गारंटी पर मुख्यमंत्री की पहल से छत्तीसगढ़ के किसानों को उनके धन का देश में सबसे उच्चतम मूल्य मिल रहा है।

आजादी के 78 साल बाद घोर माओवादी दूरस्थ गांव पूर्वता में पहली बार गूंजी दूरदर्शन की आवाज

बंगाल मङ्गू और नुप्पो झुम्मा के घर में ग्रामीणों ने देखी देश-दुनिया की खबर, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचाने की पहल

नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के विश्वकृष्णन तम छोर सुकमा जिले के अंति-माओवाद प्रभावित और दुर्ग क्षेत्र पूर्वता में विकास की एक नई किसान पहुँच के प्रभावित और सम्पादक की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुँचाने की ओर बढ़ाया गया है। आजादी के 78 साल बाद पहली बार इस गांव के लोगों ने दूरदर्शन पर देश-दुनिया की खबरें, धारावाहिक और स्थानीय फिल्में देखीं। नियद नेत्रा नांगांव पूर्वता के बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग सभी दूरदर्शन के बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग सभी दूरदर्शन के लोगों के द्वारा देखने के लिए बढ़ी टीकी सर्करों में संबंधित उपकरण का वितरण किया। परिवार को सोलर लाइट और सोलर पंखा वितरण किया गया। इसके साथ ही दूरदर्शन के सेट पूर्वती, टेकलापुडियम और सिलगेर में क्रमशः दो-दो सेट स्थापित किए गए हैं। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास को

नेशनल लोक अदालत में 22 लाख 59 हजार से

अधिक प्रकरणों का हुआ रिकार्ड निराकरण

रायपुर (विश्व परिवार)। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ राज्य में 22 लाख 59 हजार से अधिक प्रकरणों का रिकार्ड निराकरण हुआ। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कुल 842 करोड़ रुपए से अधिक का अवार्ड परित किया गया। यह यह उल्लेखनीय है कि आज 14 दिसम्बर को उच्च न्यायालय से लेकर तालुक स्तर न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन हुआ। हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के तहत खड़ाउलीय का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। यह यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की चूर्चा एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत की मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिंहा द्वारा रायपुर व दुर्ग के लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर वहाँ के प्रधान जिला न्यायाधीशों से चूर्चा की गई और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक

मार्गदर्शन दिया गया। इससे लोक अदालत के पीठासीन प्राप्तान मिला और पक्षकारों व पक्षकारों में विश्वास सुनित हुआ है।

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ को कभी बीमासु राज्य का दर्जा दिया जाता था। मध्य प्रदेश के समय से ही छत्तीसगढ़ लगातार उपेक्षित राज्य के बाबत बहुत विवेदनीय विवरणों का इलाज के लिए राज्य के बाबत जाना पड़ता था। राज्य में डाक्टरों की कमी थी। मेडिकल कालेज के नाम पर सिर्फ रायपुर ही था जहाँ से गिनती के डाक्टर ही पास होकर निकलते थे और वाँ वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नई राज्य दिखाने के लिए इसे मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य किया। हालांकि उस बाबत किंतु योजनाएँ कार्यान्वयन के लिए राज्य के बाबत जाना पड़ता था। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएँ न के बाबत जाना था। लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य के बाबत जाना पड़ता था। राज्य में डाक्टरों की कमी थी। मेडिकल कालेज में राज्य के बाबत जाना था। राज्य में डाक्टरों की कमी थी। मेडिकल कालेज के नाम पर सिर्फ रायपुर ही था जहाँ से गिनती के डाक्टर ही पास होकर निकलते थे।

साल 2003 में छत्तीसगढ़ में एक नयी सुबह की हुई और यहाँ से छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षण के क्षेत्र में धीरे-धीरे आगे बढ़ा दिया। बीते दो दशकों के सफर में एक नया राज्य जो बहुत जाना चाहिए था। राज्य में डाक्टरों की कमी थी। मेडिकल कालेज के नाम पर सिर्फ रायपुर ही था जहाँ से गिनती के डाक्टर ही पास होकर निकलते थे। इसी राज्य के बाबत जाना चाहिए था। राज्य में डाक्टरों की कमी थी। मेडिकल कालेज के नाम पर सिर्फ रायपुर ही था जहाँ से गिनती के डाक्टर ही पास होकर निकलते थे।

रायपुर (विश्व परिवार)। राज्य सासान की श्रीरामलला दर्शन योजना से प्रदेश के हजारों लोगों का सपना पूरा हो रहा है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों को निःशुल्क अयोध्या धाम की यात्रा करवा रही है। विशेष द्वेषों से ब्रह्मालुओं को अयोध्या ले जाकर श्रीरामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराया जाता है। दोनों यात्राओं का यात्रा से संबंधित जारी रहा है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने निःशुल्क अयोध्या धाम की यात्रा के लिए एक सीटें भी 100 से बढ़कर 1460 हो गयी हैं। शासकीय मेडिकल कालेजों में 291 स्थानकोत्तर की सीट



सुशासन
का साल
छत्तीसगढ़
हुआ अवृश्वालू

खेलों के जरिए
सुखद भविष्य
की ओर बढ़ता
बस्तर



खेलेगा बस्तर
बढ़ेगा बस्तर

श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार

हमने बनाया है

हम ही सँवारेंगे



Q.R. स्कैन करें

f x i o ChhattisgarhCMO
Visit us: f x DPRChhattisgarh

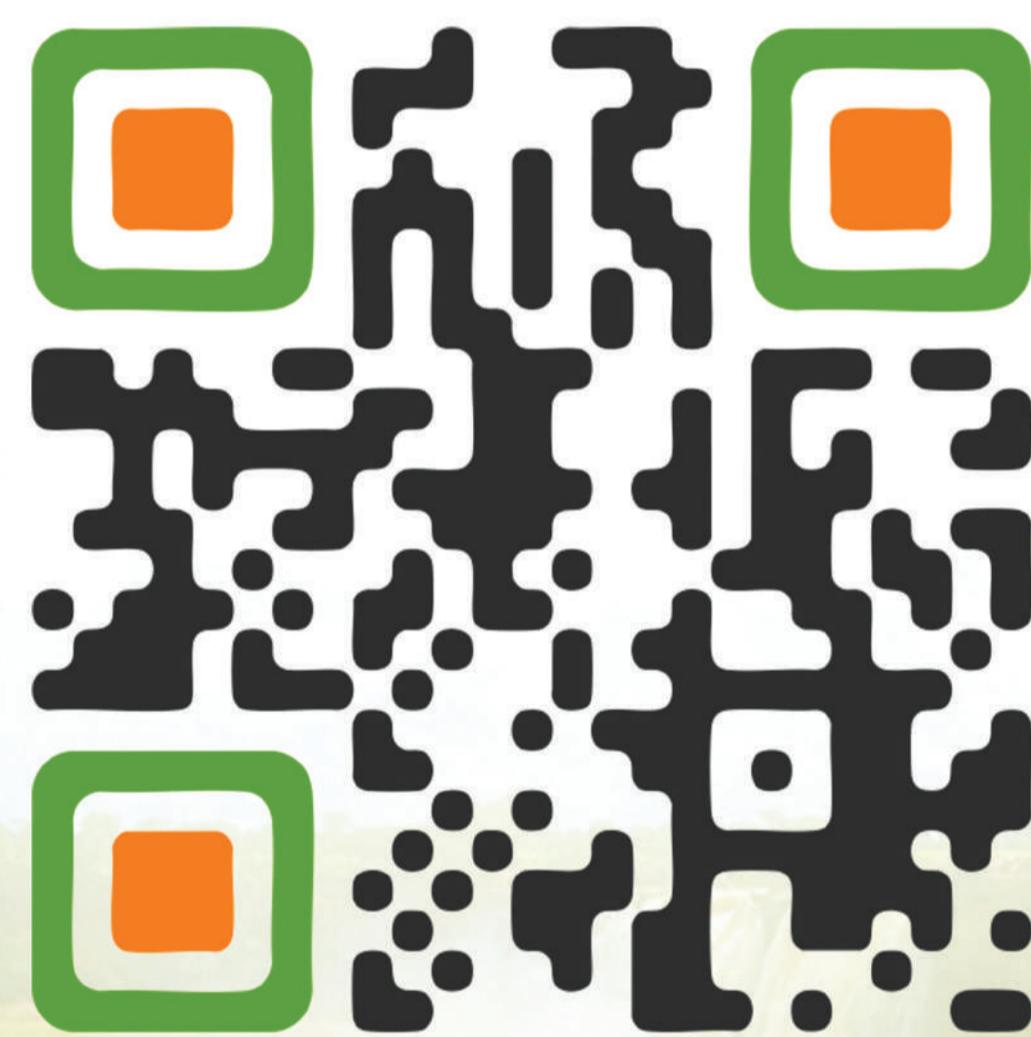
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
www.dprcg.gov.in



बस्तर ओलंपिक 2024



श्री विष्णु देवसाय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



+
नया बस्तर देखने के लिए स्कैन करें



+
श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार



+
श्री विलास देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

संपादकीय

अवैध प्रवेश की कोशिश में बढ़ोत्तरी

कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध प्रवेश की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 22 फीसदी बढ़ोतरी हुई थी। कनाडा के रास्ते ऐसे कुल 1,09,535 प्रयास हुए, जिनमें 16 प्रतिशत में भारतीय शामिल थे। गुजरे हफ्ते राज्यसभा में इस प्रश्न का विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जवाब नहीं दिया कि क्या भारत से गैर-कानूनी ढंग से बाहर जाकर आश्रय मांगने वाले लोगों की संख्या में 800 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। सिंह ने कहा कि सरकार के पास इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये लोग जिन देशों में जाते हैं, वहां की सरकारें उन्हें साझा नहीं करतीं। मगर उन्होंने यह जरूर कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। बहरहाल, अब एक आंकड़ा जरूर सामने आया है, जिसे भारत सरकार के नजरिए से देश के लिए अपमानजक कहा जाएगा। ये सूचना अमेरिका के कस्टम और सीमा सुरक्षा विभाग ने दी है। उसके मुताबिक कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध प्रवेश की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 22 फीसदी बढ़ोतरी हुई थी। कनाडा के रास्ते ऐसे कुल 1,09,535 प्रयास हुए, जिनमें 16 प्रतिशत में भारतीय शामिल थे। उसके पहले वाले वर्ष में 30,010 भारतीयों ने ऐसी कोशिश की थी, जबकि उपरोक्त अवधि में यह संख्या 43,764 हो गई। और यह सिर्फ कनाडा के रास्ते हुए प्रयासों का आंकड़ा है और वह भी सिर्फ उनसे संबंधित है, जिन्हें ऐसी कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अमेरिका में ऐसी घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिशें मैक्सिसको की तरफ से होती हैं। अब चूंकि अवैध आव्रजकों को देश से निकालना और अवैध आव्रजन रोकना निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो यह मुद्दा चर्चा में आया है। वैसे भारत से बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से जाकर विदेश में बसने की कोशिश कर रहे हैं, यह आम जानकारी है। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी कोशिशों अवसर साधन संपत्ति वर्ग के लोग शामिल होते हैं। क्यों? मान-अपमान की सोच से बाहर निकल सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आखिर क्यों विदेश में बसाने के लिए 80 लाख रुपये तक एंजेंटों को देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं? देश में मौजूद अवसरों के प्रति लोगों का विश्वास इतना क्यों डोल गया है, सूचने का मुद्दा यह है।

आलेख

भाजपा की निर्णायक लड़ाई का निष्कर्ष

अजीत द्विवेदी

संसद के शांतकालान सत्र में हर दिन राजनातक का नया रण दखन को मिल रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने किसी हाल में अडानी का मुद्दा नहीं छोड़ने का फैसला किया है तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा भी निर्णायक लड़ाई की तैयारी में है। भाजपा की निर्णायक लड़ाई का निष्कर्ष यह है कि लोकसभा में यानी जनता के संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गद्दार' हैं, सबसे बड़े विपक्षी पार्टी कांग्रेस की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी देश विरोधी हैं और अमेरिका दुश्मन देश है। भाजपा ने संसद की बहस और चर्चाओं के साथ साथ प्रेस कांफ्रेंस करके भी यह नैरेटिव स्थापित किया है। जब भाजपा के सांसदों ने आरोप लगाए तब भी ये आरोप गंभीर थे लेकिन अब तो केंद्र सरकार के मत्रियों ने भी इन आरोपों को दोहराया है। तभी यह सवाल गंभीर हो गया है कि क्या सचमुच नेता प्रतिपक्ष गद्दार' या देश विरोधी हैं और क्या सचमुच अमेरिका भारत का दुश्मन है? पहले अमेरिका पर लगाए गए आरोपों की चर्चा करें तो उसमें कई बातों का खुलासा हो गया है। भाजपा के सांसदों ने जब कहा कि ओसीसीआरपी यानी आर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करण्यान रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इस संस्था को अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी विदेश विभाग की फॉर्डिंग मिलती है तब अमेरिका ने इस पर अपना पक्ष रखा था। अमेरिका ने कहा था कि वह मीडिया की स्वतंत्रता का चैंपियन रहा है और इस तरह के किसी भी संगठन पर दबाव नहीं बनाता है। इतना ही नहीं अमेरिका ने इसे निराशाजनक बताया था कि भारत में सत्तारूढ़ दल इस किस्म के आरोप लगा रहा है। अब सवाल है कि भाजपा ने ये आरोप किस आधार पर लगाए थे? भाजपा का आरोप फांस के मीडिया समूह %मीडियापार्ट' की एक रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें कथित तौर पर यह कहा गया था कि ओसीसीआरपी को अमेरिकी विदेश विभाग की फॉर्डिंग है। अब %मीडियापार्ट' ने जबाब दिया है और कहा है कि भारत में सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा %फेक न्यूज' फैला रही है। उसका कहना है कि उसकी

श्रुति व्यास

मनमानी और लोगों को दबा कर शासन करने वालों का राज एक न एक दिन खत्म होता ही है। और जब उनके राज का अंत होता है तो वह निष्ठुर होता है। और उन देशों में भी जहां लोकतंत्र दिखावे का है। हाल के दशकों पर निगाह डालें। शेख हसीना का क्या हुआ? सद्दाम हुसैन, गद्वाफी, जीन अल अबिदान बेन अली, होस्ती मुबारक आदि की सूची में अब बशर अल-असद का नाम भी जुड़ गया है। असद परिवार के पचास साला राज के खात्मे का सभी और स्वागत है। सीरिया में लोगों ने राहत की सांस ली। वहां %एक नई शुरूआत' और बाकी दुनिया से नए सिरे से संबंध कायम करने को लेकर जश्न का माहौल है। पश्चिम ने असद सरकार के तख्तापलट पर अपनी प्रसन्नता और हर्ष बेबाकी से जाहिर की है। लेकिन एक ऐसे देश के लिए नई शुरूआत कैसी होगी जिसने सिर्फ निर्ममता भुगती है? वे एक नई शुरूआत कैसे करेंगे जबकि उन्होंने जीवन भर सिर्फ दमन देखा-भोगा है? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस्लामिक उग्रवादियों और आतंकवादियों का गठबंधन %ताजी शुरूआत' का प्रतीक भला कैसे बन सकता है? भविष्य में वे क्या करेंगे यह कोई नहीं जानता। ऐसे में क्या इनके सत्ता पर काबिज होने का जश्न मनाया जाना चाहिए? दस साल पहले मिस्र, लीबिया, टायूरीशिया और यमन झ़ जहां तानाशाहों का तख्ता पलट दिया

गया था झ़ु में खुशियां मनाई गई थीं और सुनहरे, आजादी भरे दिनों का इंतजार था। उम्मीदों का कोई ठिकाना न था। सारी दुनिया ने तानाशाहों का राज खत्म होने की थी। ये चार देश क्रांति की सफलता की नजीर बन गए थे। उसे अरब स्प्रिंग कहा गया था। लेकिन आज इन देशों में जो हालात हैं वे हमारे लिए एक चेतावनी हैं। मिस्र में लोकतंत्र अधिक समय तक कायम न रह सका। लीबिया, ट्यूनीशिया और यमन गृहवृद्ध में फंस गए। ये विदेशी ताकतों का अखाड़ा हुए। खाड़ी के अमीर देशों ने वहां अपने लोगों को सत्ता पर कबिज कराने और अन्य देशों में अलोकतांत्रिक शक्तियों की मदद के लिए बेशुमार पैसा खर्च किया। आज इस क्षेत्र में 2010 से भी कम आजादी है झ़ु और ज्यादातर पैमानों पर इन देशों के हालात खराब ही हैं। लोकतंत्र के झ़ंडाबरदार पश्चिमी देश, इन देशों की नई शुरुआत में मददगार नहीं हुए। जैसा कि अफगानिस्तान के मामले में हुआ, अब वे इस सोच-विचार में ढूबे हुए हैं कि उन देशों में बगावत को सफल बनाने के लिए वे क्या कर सकते थे। क्या इससे ज्यादा आतंकमुग्ध होना संभव है? जो हुआ उसकी वजह बहुत और सीधी है। बगावत के बाद ईरान से रूस तक, और पश्चिम देशों से लेकर तक क्षेत्रीय ताकतों तक झ़ु सभी इन देशों में अपना दबदबा कायम करने में जुटे। इसके अलावा, इस्लामवादी समूह भी सक्रिय थे जो चाहते थे कि उनकी मर्जी चले और सत्ता पर उनका प्रभाव रहे। लेकिन सबसे बड़ी भूल हालातों को समझने में हुई।

लोकतंत्र के लिए मात्र यह पर्याप्त नहीं होता कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हों। उसके लिए बातों को समझने, जानने और उनमें रूचि लेने वाले नागरिकों सभी पक्षों को स्वीकार्य नियम-कानूनों और इस सांझे भरोसे की भी ज़रूरत होती है कि राजनैतिक मतभेद देश के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बनेंगे सीरिया पर असद का राज खत्म होना एक राहत भर्त खबर है लेकिन अनिश्चितता के हालात हैं। इस्लामिक उग्रपंथियां का गठबंधन एक बड़ा खतरा है। हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस), जिसकी इस तखापलट में सबसे बड़ी भूमिका थी, कार्फ़ शक्तिशाली है। अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। देश में अपना दबदबा कायम करने के लिए एचटीएस को एक अन्य तुर्की-समर्थित संगठन, जिसका प्रभाव क्षेत्र उत्तरी सीरिया है, और कुर्दिश नेतृत्व वाले पूर्वी सीरिया के एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है, से निपटना होगा। हालांकि एचटीएस अपनी छवि एक उदारवादी और नर्मदिल संगठन की बनाने की कोशिश कर रहा है, जो ईसाईयों, द्रुसें और असद के समर्थन के मुख्य आधार शिय समुदाय के अलावतियों समेत सीरिया के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब असद के बाद के दौर के सीरिया के शासन के संचालन के संबंध में इन समुदायों के साथ इस संगठन का कोई समझौता हो। यदि ऐसा नहीं हुआ

तो गृहयुद्ध चलता रहेगा क्योंकि विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के लड़ाके, नई केन्द्रीय सरकार को अपने-अपने इलाकों में घुसने से रोकने के लिए खड़े हो जाएंगे। जहां तक विदेशी शक्तियों का सवाल है, तुर्की ने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। तुर्की, सीरिया में राजनैतिक स्थिरता इसलिए भी चाहता है क्योंकि तुर्की में रह रहे 30 लाख सीरियाई शरणार्थी तब तक अपने देश वापिस नहीं जाएंगे जब तक वहां से असद का नामोनिशां मिट नहीं जाता। राष्ट्रपति अर्दोंगान को शरणार्थियों को वापिस भेजने में असफल रहने के लिए देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तुर्की किस सीमा तक एचटीएस को अपने नियंत्रण में रख सकेगा, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। अर्दोंगान का एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल-जोलानी पर कितना प्रभाव है, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ईरान और रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी और वे कौन-से कदम उठाएंगे, यह समय बताएगा। ईरान का मानना है कि एचटीएस के सशक्त होने और आगे बढ़ने में इजराइल और अमेरिका का मुख्य योगदान रहा है। उसका दावा है कि इजराइल इस संघर्ष का लाभ उठाकर सीरिया के रास्ते ईरान से लेबनान पहुंचाए जाने वाले हथियारों के मार्ग को बंद करना चाहता है। यह बात सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर कही जा रही है, खासकर शियाओं द्वारा। सीरिया का घटनाक्रम निश्चित ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा।

भाजपा के खिलाफ 27 में फिर बदलेगा समीकरण

अजय कुमार

कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां तब और बढ़ गईं जब सपा कि तरफ से कहा जाने लगा कि ईंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जगह तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को दिए जाने पर सपा को एतराज नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक बार पिर से सियासी समीकरण काफ़ी तेजी के साथ बदल रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की विरोध की हाँड़ी नहीं पक पाने के कारण प्रदेश में एक बार पिर से नए सियासी समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं। इस नये समीकरण में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का अहम रोल हो सकता है। इसी बजह से समाजवादी पार्टी ईंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दिये जाने की मांग का भी समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव के समय तक समाजवादी पार्टी कांग्रेसी पंजे से अपना हाथ छुड़ाकर ममता बनर्जी के कहने पर एक बार पिर से मायावती के सात बुआ भूतीजे वाला रिश्ता निभाते नजर आए। ऐसा होता है तो यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यह संभावना है इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों या महीनों से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में

संधमरा का काशश कर रहा है। सपा-कांग्रेस के बीच दूरियां लगातार बढ़ने के साथ एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी भी हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की नाकामी भी इसमें एक अहम कड़ी समझा जा रहा है। यही दूरियां ही हैं कि संसद के अंदर भी सपा-कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर मजबूती से एक साथ नहीं दिख रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस तरह विरोध नहीं किया जैसी उससे अपेक्षा थी। बताते हैं कि लोकसभा में फैजाबाद (अयोध्या) के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सीट पौछे हाने पर भी दोनों दलों के रिश्तों में दरार आई है। सपा का मानना है कि सीटिंग प्लान पर बात के समय कांग्रेस ने उसे भरोसे में नहीं लिया। वहीं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सदन में अदाणी मामले में उसे सपा का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि जेल में बंद सपा के कदावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने भी ईंडिया ब्लॉक को जेल से एक संदेश भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि ईंडिया ब्लॉक को मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लिखा कि संभल की घटना के जैसे ही रामपुर में हुए अत्याचार का मुद्दा भी



संसद में उतनी है चाहिए। कांग्रेस अंत तब और बढ़ गई जा जाने लगा कि इंडियन कांग्रेस की जगह सुप्रीमो ममता बनर्जी को एतराज नहीं चुनाव के बाद कई लगातार हार के बाये अंतर्विरोध बढ़ रहे थे कि चर्चा यह भी है कि बार पिछ पलट सकता है कि बीच आई दूरिये रुख नई राजनीतिक सकता है। बहराल, है कि संभल मामले

मजबूती से उठाना
सपा के बीच दूरियां
सपा कि तरफ से कहा
गठबंधन का नेतृत्व
तृणमूल कांग्रेस की
को दिए जाने पर सपा
बता दें लोकसभा
वनावों में कांग्रेस की
इंडिया गठबंधन में
हैं। उधर दूसरी तरफ
एपी की राजनीति एक
है। सपा और कांग्रेस
के बीच मायावती का
मीकरणों को जन्म दे
पा नेताओं का कहना
में उसके सांसद पर

A large crowd of people holding orange flags with the RSS logo, participating in a rally.

